सरकारी स्कूलों को सुधारने का अभियान

भारत डोगरा

जहां एक ओर सरकारी स्कूलों में अध्यापकों व सुविधाओं का अभाव बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में 'नींव-शिक्षा का सवाल' अभियान ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कई स्थानों पर इस अभियान के सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।

इस अभियान की एक विशेषता यह है कि यह सामाजिक कार्यकर्ताओं व मीडिया के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस अभियान में एक ओर राजस्थान का एक प्रमुख समाचार पत्र '*राजस्थान पत्रिका*' है तो दूसरी ओर सूचना व अधिकार अभियान (एस.आर. अभियान) है जिसमें राजस्थान के लगभग 100 संगठनों व संस्थानों की भागीदारी है। जहां एक ओर *राजस्थान पत्रिका* के पत्रकार व अन्य प्रतिनिधि राजस्थान के सभी भागों में उपस्थित हैं, वहीं एस.आर. अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी राजस्थान के दूर-दूर के गांवों में मौजूद हैं।

इस तरह किसी सार्थक अभियान को चलाने में समाचार पत्र व सामाजिक कार्यकर्ताओं का आपसी सहयोग बहुत उपयोगी हो सकता है। नींव अभियान को जिस तरह राजस्थान पत्रिका व एस.आर. अभियान ने मिल कर चलाया है, उससे सार्थक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मीडिया व सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग का एक मॉडल भी विकसित होता है जिसे आगे अन्य सामाजिक महत्व के उद्देश्यों के लिए भी अपनाया जा सकता है।

नींव अभियान को मई-जून 2015 के आसपास आरंभ किया गया था, हालांकि इसकी तैयारियां तो इससे काफी पहले से ही आरंभ हो गई थीं। यह अभियान लगभग एक वर्ष तक चलेगा और पूरी उम्मीद है कि इसके फलस्वरूप सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी हद तक सुधरेगी तथा भविष्य के लिए और भी अधिक संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

आगे के लिए उम्मीद का आधार यह है कि इस अभियान के दौरान सरकारी स्कूलों की स्थिति में जन भागीदारी बहुत बढ़ रही है। दूर-दूर के गांवों में भी जन साधारण सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। इसी से उम्मीद बंधती है कि इस वर्ष सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की जो शुरुआत इस अभियान से हुई है वह आगे भी जारी रहेगी।

इस अभियान में सूचना व रोज़गार अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं, *राजस्थान पत्रिका* के प्रतिनिधियों, कॉलेज छात्रों आदि की एक मुख्य भूमिका है कि वे सरकारी स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों को स्कूलों में सुधार लाने में भागीदारी के लिए प्रेरित करें तथा इस बारे में मार्गदर्शन भी करें।

इस तरह सभी गांवों व शहरों में सभी सरकारी स्कूलों से जुड़े हुए सक्रिय नागरिकों के समूह तैयार हो रहे हैं जो एक वर्षीय अभियान के बाद भी स्कूलों में सुधार के प्रयास जारी रखेंगे।

इन नागरिकों, कार्यकर्ताओं व पत्रकारों ने स्कूलों में उपलब्ध ज़रूरी सुविधाओं का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में स्कूलों के बारे में यह जानकारी प्राप्त की गई कि वहां अध्यापकों के कितने पद हैं? कितने पद खाली हैं? कितने छात्रों के लिए कितने अध्यापकों की व्यवस्था इस समय है? छात्रों की उपस्थिति कितनी है? स्कूल में कितनी कक्षाओं के लिए कितने कमरे हैं? खेल का मैदान है कि नहीं व उसकी स्थिति कैसी है? चारदीवारी है कि नहीं? छात्रों, छात्राओं व स्टाफ के लिए शौचालय की स्थिति कैसी है? साफ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है कि नहीं? स्कूल प्रबंधन समिति की स्थिति कैसी है?

इन सब सुविधाओं व अध्यापकों की उपलब्धि के बारे में सवाल सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी स्कूलों से पूछे गए। इस तरह जो जानकारी मिली उसके आधार पर समाचार पत्र के विभिन्न संस्करणों में सैंकड़ों रिपोर्ट नियमित प्रकाशित की गईं। इनसे स्कूलों की वास्तविक स्थिति का

पता चला।

फिर राजस्थान में मौजूद सुनवाई के अधिकार कानून के अंतर्गत विभिन्न मूल सुविधाओं के उपलब्ध न होने की शिकायतें सरकारी अधिकारियों के पास दर्ज की गईं। विभिन्न ब्लाकों में कुछ पंचायतों समूहों में स्कूली शिक्षा पर नागरिक समितियों का गठन किया जा रहा है। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है जिससे वे शिक्षा के अधिकार के उचित क्रियान्वयन की अपनी ज़िम्मेदारी सही ढंग से निभा सकें। इसके लिए उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके बाद लगभग 100 दिनों की शिक्षा यात्रा का आयोजन सभी ज़िलों में किया जाएगा। इस दौरान स्कूली शिक्षा में सुधार पर व्यापक स्तर पर जन-संपर्क होगा।

उपलब्ध जानकारियों के आधार पर सरकारी अधिकारियों से बातचीत का सिलसिला भी आरंभ हो गया है जिसमें उन्होंने अनेक आश्वासन दिए हैं व कुछ स्थानों पर असरदार कार्रवाई भी हुई हैं। यह संवाद आगे और व्यापक स्तर पर होगा। विभिन्न संभागों में इन संवादों को चलाने के लिए *राजस्थान पत्रिका* व सूचना-रोज़गार के अधिकार के अभियान प्रतिनिधियों की टीम भी बन रही है। सबसे अधिक शिकायतें अध्यापकों की कम संख्या के बारे में प्राप्त हो रही हैं।

इस मुद्दे पर जन-जागृति की सीधी अभिव्यक्ति छात्रों व अभिभावकों द्वारा अनेक स्कूलों की तालाबंदी के रूप में नज़र आई है। अध्यापकों व बुनियादी सुविधाओं के अभाव से त्रस्त छात्रों व उनके अभिभावकों ने अपनी मांगों पर बहुत समय से कोई कार्रवाई न होने पर नींव अभियान के अंतर्गत स्कूलों को ताला लगा दिया व अधिकारियों को कहा कि अध्यापकों व बुनियादी सुविधाओं सम्बंधी मांग पूरी होने पर ही स्कूल फिर से खुल सकेगा। ऐसी लगभग 300 घटनाएं हाल के सप्ताहों में राजस्थान के स्कूलों में हो चुकी हैं। इनमें से अधिक स्कूल लड़कियों के स्कूल हैं। पक्के आश्वासन मिलने के बाद ही स्कूल फिर खुल सके।

उम्मीद है कि इस अभियान के दौरान सरकारी स्कूलों के सुधार में जन भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा इस अनुभव से सीखते हुए अन्य राज्यों में भी इससे मिलते-जुलते जन अभियान आरंभ हो सकेंगे। ***(स्रोत फीचर्स)***